Improvement of Railway Stations in Punjab, Uttar Pradesh and Bihar

*229. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the steps being taken by Government for improvement of railway stations in the States of Punjab, Uttar Pradesh and Bihar; and

(b) the details thereof?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों का सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए हर वर्ष जरूरत पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार प्राय: सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, जो धन की उपलब्धता और स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तदनुसार, 15-15 लाख रूपए से अधिक की लागत के सुधार संबंधी कार्य पंजाब में 5 स्टेशनों, उत्तर प्रदेश में 13 स्टेशनों और बिहार में 16 स्टेशनों पर शुरू किये गये हैं। इसके अलावा, 15 लाख रूपये से कम की लागत के कार्य भी विभिन्न सटेशनों पर शुरू किये गये हैं।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: महोदय, मिनिस्टर साहब ने पंजाब के लिए रेलवे स्टेशनों के बारे में बतलाया कि हमने उनको माडरेट करने के लिए कितना कितना रूपया नियुक्त किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाब में शाहबाद एक रेलवे स्टेशन है जहां से एशिया में सबसे ज्यादा काली मिर्च चलती है। इसी तरह पंजाब में लुधियाना है जहां से होजरी का काम दुनिया में जाता है। लेकिन यहां पर न तो वेटिंग रूम है, न ही कोई टायलेट का इंतजाम है, न ही रिजरवेशन का कोई इंतजाम है। प्लेटफार्म जो वही अंग्रेजों के पहले, 1947 के पहले था वही है। तो इनको माडरेट करने के लिए कितना रूपया आपने रखा है यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री सतपाल महाराज: माननीय सभापति महोदय, हमारे रेलवे की सुविधाएं दो प्रकार की होती है - आधारभूत और अतिरिक्त। जो माननीय सदस्य ने बताया है वह कोई छोटा रेलवे स्टेशन हैं उसके बारे में जो सूचना है वह इस समय उपलब्ध नहीं है। वह माननीय सदस्य को प्रेषित कर दी जाएगी।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: नहीं सर, मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि लुधियाना और शाहबाद को माडरेट करने के लिए आपने कितना-कितना रूपया मुकर्रर किया है?

श्री सतमाल महाराज: वह सूचना अभी इस समय नहीं है। आपको प्रेषित कर देंगे। आपको भेज देंगे सूचना।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। माननीय रेलवे मंत्री साहब जो है वे कहते है कि हम जो ऐलान करने हैं उसको पूरा करते है। हमारे यहां एक शताब्दी चली है जो दिल्ली से अमृतसर जाती है। उसके लिए हमने बोला है, लिखकर भी भेजा है कि दिल्ली से लुधियाने के लिए इसमें चार घंटे का सफर है। दिल्ली से चलती है तो लुधियाने में यह ट्रेन ठहरती है। इस लम्बे सफर में उस ट्रेन में कोई भी फर्स्ट एड नहीं है। कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाए या सर्दी हो तो उस ट्रेन में कम्बल भी नहीं है। उसके लिए मैंने आपको लिखकर भेजा था। ऐसी एक बात हो चुकी है। पहले हमारे एक एम.पी. थे श्री सतपाल मित्तल। ऐसे ही उनकी मौत हो गयी थी। ऐसे ही चले थे स्टेशन से और उनकी मौत हो गयी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने ऐलान किया था कम्बल देने का और फर्स्ट एड देने का। जो हमारे डिब्बे हैं वे बनाते तो हम हैं लेकिन इतने गंदे हैं कि चलते ही नहीं।

श्री सतपाल महाराज: सभापति महोदय, रेलों के अंदर जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिए हैं उनका धीरे-धीरे हम लोग विस्तार कर रहे हैं और जो सुविधाएं उन्होंने बतायी हैं निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: हम तो यह कहते हैं कि आप ऐलान कर चुके हैं, बड़े वजीर साहब - पासवान जी ने ऐलान किया है हाउस में। वह अखबारों में छपा है। उस छपे हुए ऐलान पर क्या अमल हुआ यह जानना चाहता हूं।

श्री सतपाल महाराज: धीरे-धीरे अमल हो रहा है और आपसे बातचीत करके हम लोग ...(**व्यवधान**) करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

निरक्षरता के संबंध में सम्मेलन

*222. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निरक्षरता की समस्या पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों का हाल ही में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस सम्मेलन में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने से संबंधित साक्षरता अभियानों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में 10 अगस्त, 1996 को राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया जबकि ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 4-5 जुलाई, 1996 को बुलाए गए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार सहित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर चर्चा की गई।

राज्य शिक्षा मंत्रियों ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को जारी रखने तथा नई शताब्दी की शुरूआत होने तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षा में सरकारी निवेश को बढ़ाने से संबंधित केन्द्र सरकार की पहलों का स्वागत किया। सम्मेलन में 2005 तक सबको साक्षर बनाने के संदर्भ में प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को सफल बनाने में प्रौढ साक्षरों द्वारा निभाई जाने वाली उत्प्रेरक भूमिका को स्वीकार किया गया।

सम्मेलन में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अपेक्षित संसाधनों का पता लगाने के लिए तथा निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु रूपात्मकताएं तैयार करने के लिए राज्य शिक्षा मंत्री श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है।

Hike in the prices of Commonly used medicines

*223. SHRI SATISH PRADHAN:
SHRI VAYALAR RAVI:

Will the MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that retail prices of 21 commonly used drugs have shown sharp increase in the last 20 months; as reported in the "The Hindustan Times" dated the 12th November, 1996;

(b) if so, the reaction of the Government to the observations made therein and facts of the matter;

(c) the details of action taken/proposed by the Government through National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA); and

(d) the justification for upward spurt in prices of essential/commonly used drugs?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) and (b) The Ministry undertakes periodic studies to compare prices of formulations. In the latest such study it has been found that prices of 21 formulations had gone up. However, it would not be correct to say that all these are commonly used formulations.

(c) The National Pharmaceutical Pricing Authority is yet to start functioning. However, whenever instances of price violations in price controlled formulations are noticed in the Department, action under DPCC, 1995 and Essential Commodities Act, 1955 is taken through the State Drug Controllers.

(d) Increase in the prices of bulk drugs, excepients, utilities, cost of packaging, fluctuation in foreign exchange rate for imported items, changes in excise duty etc. have been found to be the prime factors for increase in the prices of medicines.

Poultry and Dairy in the Cooperative Sector

*226. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether Government are still encouraging poultry and dairy in the cooperative sector;

(b) if so, the details of the schemes;

(c) the overall plan of Government in this regard and by when it is likely to be realised; and

(d) how our position in this field compares with other developed countries?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir. The National Cooperative Development Corporation (NCDC) has been providing assistance to